साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 16 मार्च से 22 मार्च 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 04 में...
हाथी संरक्षण पर सवाल, छह साल में 70 हाथियों की मौत

पेज 12 में...
न एट्रेस इंडेक्स, न टैक्स अपराध को मिल रहा बढ़ावा

वर्ष : 02 अंक : 02 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 07 आईपीएल में आखिरी बार खेलेंगे तीन दिग्गज खिलाड़ी

'उड़ता छत्तीसगढ़' की आहट!

धान के कटोरे में अफीम का 'स्टार्टअप', सरहद से सत्ता तक गहराता नशे का जाल

दुर्ग से बलरामपुर तक करोड़ों की अफीम का भंडाफोड़

आखिर पटवारी और कृषि अधिकारियों की आंखों पर किसने बांधी पट्टी? रसूखदारों के फार्म हाउस बने 'सेफ हेवन'

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

छत्तीसगढ़, जिसे हम 'धान का कटोरा' कहते आए हैं, वहां अब खेती का एक ऐसा 'नशा' पैर पसार रहा है जिसकी कल्पना भी डरावनी है। दुर्ग के हाई-प्रोफाइल भाजपा नेता के फार्म हाउस से लेकर बलरामपुर के दुर्गम पहाड़ों तक अफीम की लहलहाती फसल ने पूरे सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधानसभा से लेकर सड़क तक मचे हंगामे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ नशे के सौदागरों के लिए 'नया स्टार्टअप' हब बन गया है?

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान अब तक 'धान के कटोरे' के रूप में थी, जहाँ की माटी से उपजा अनाज करोड़ों लोगों का पेट भरता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दुर्ग के पॉश फार्म हाउसों से लेकर बलरामपुर की दुर्गम पहाड़ियों तक जो 'नया स्टार्टअप' लहलहाता मिला है, उसने सत्ता के गलियारों से लेकर सरहद तक हड़कंप मचा दिया है। यह नई किसानी धान की नहीं, बल्कि उस अफीम की है जिसकी एक ग्राम की कीमत बाजार में सोने के भाव को टक्कर देती है।

अजीब विडंबना है कि जहां एक ओर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए संघर्ष करता है, वहीं नशे के सौदागरों ने छत्तीसगढ़ की उर्वर भूमि पर 'मनी ऑन सेट प्राइस' (तय कीमत पर मोटा मुनाफा) का ऐसा जाल बुना कि सरकारी तंत्र की आंखों पर 'अफीम की पट्टी' बंध गई। भाजपा नेता के फार्म हाउस पर अफीम का मिलना और झारखंड के 'पिंटू दांगी गैंग' का छत्तीसगढ़ कनेक्शन यह साफ करता है कि यह महज कुछ खेतों की कहानी नहीं, बल्कि 'उड़ता छत्तीसगढ़' की एक डरावनी पटकथा है। आखिर कैसे पटवारियों की गिरदावरी रिपोर्ट में अफीम 'मक्का' बन गई? कैसे रसूखदारों के फार्म हाउस ऐय्याशी और नशे के 'सेफ हेवन' बन गए? और क्या सरकारी सर्वे इस गहरे सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंच पाएगा?

सिंडिकेट का 'मास्टर प्लान'
200 किमी दूर झारखंड की जेल से कंट्रोल

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का रिमोट कंट्रोल झारखंड के चतरा जिले और वहां की जेल में बंद पिंटू दांगी गैंग के पास है।

रणनीति: तस्करों ने छत्तीसगढ़ के उन दुर्गम इलाकों को चुना जहां सड़क नहीं है और झारखंड की सीमा महज 50 मीटर दूर है।

ट्रेनिंग: स्थानीय किसानों को अफीम उगाने की ट्रेनिंग झारखंड में दी गई।

प्रोसेसिंग: छत्तीसगढ़ की जमीन सिर्फ 'कच्चे माल' के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स बिहार और झारखंड में सक्रिय हैं।

छत्तीसगढ़ के खेतों में उगता 'जहरीला स्टार्टअप'

प्रशासनिक फेल्योर: 'एजेंट' चला रहे हैं पटवारी राज

अफीम की खेती रातों-रात नहीं हुई। यह राजस्व और कृषि विभाग की सामूहिक विफलता है।

गिरदावरी का खेल

अक्टूबर में हुए सर्वे में पटवारियों ने मौके पर जाने के बजाय दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट बनाई। जहां अफीम थी, वहां कागजों में 'कटी हुई फसल' दिखाई गई।

पटवारी-एजेंट नेक्सस

अधिकांश पटवारियों ने निजी तौर पर 'एजेंट' रखे हैं। इन्ही एजेंटों की गलत रिपोर्ट पर अधिकारी सील-ठप्पा लगाते रहे।

दुर्ग में एक्शन

कलेक्टर ने कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित किया है क्योंकि जिस जमीन पर मकई दिखाने का दावा था, वहां अफीम फल-फूल रही थी और उसी जमीन पर बैंक से लोन भी ले लिया गया।

फार्म हाउस या ऐय्याशी के अड्डे

दुर्ग कांड ने प्रदेश के 1000 से ज्यादा फार्म हाउसों की कुंडली खोल दी है। सफेदपोशों की ढाल: रायपुर, दुर्ग और धमतरी के आसपास आईएएस, आईपीएस और बड़े राजनेताओं के फार्म हाउस हैं। नियमतः 10% से ज्यादा निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहां लग्जरी कमरे, स्विमिंग पूल और हॉल बनाकर शराब और जिस्म का कारोबार फल-फूल रहा है। अफीम कांड के बाद अब अफसर खुद अपने फार्म हाउसों का मुआयना करने को मजबूर हैं।

MSP का नया मतलब: 'मनी ऑन सेट प्राइस'

किसानों के लिए MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) जीवनदान होता है, लेकिन नशे के इस कारोबार में इसका मतलब बदल गया है। अफीम की काली कमाई किसी भी अनाज से कई सौ गुना ज्यादा है। यही वो 'नया नशा' है जिसने दुर्ग और बलरामपुर की उर्वर मिट्टी को तस्करों की पहली पसंद बना दिया है।

दूध (अफीम): ₹50,000 प्रति किलो।
डोडा (छिलका): ₹20,000 प्रति किलो।
खसखस (दाने): ₹2,000 प्रति किलो।
हेरोइन (प्यूरीफाइड): अंतरराष्ट्रीय बाजार में ₹2 करोड़ प्रति किलो तक।

क्यों मुफीद हुई छत्तीसगढ़ की धरती

अफीम तस्करों ने छत्तीसगढ़ को ही अपना 'नया हब' क्यों बनाया? इसके पीछे राज्य की खास भौगोलिक और बाजार की स्थितियां हैं:

अभेद्य भूगोल

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, जिसमें घने जंगल, नदियों के तराई क्षेत्र और छोटी-छोटी नदियाँ हैं, तस्करों को छिपने की जगह देती है। दुर्गम पहाड़ों तक प्रशासन की पहुंच न होना उनके लिए वरदान साबित हुआ।

कम पानी, ज्यादा मुनाफा

अफीम की पैदावार के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। नदियों के किनारे वाली 'शीतलता' (Moisture) ही इस फसल के लिए पर्याप्त आधार बन जाती है।

ट्रांसपोर्ट का 'गोल्डन गेट'

दुर्ग के अलावा अंबिकापुर और सूरजपुर ऐसे जिले हैं, जिनकी सीमाएं दूसरे राज्यों (झारखंड-बिहार) से सटी हैं। यहाँ से झारखंड-बिहार के रास्ते नेपाल तक अफीम पहुँचाना तस्करों के लिए बच्चों का खेल बन गया है।

कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन

प्रशासनिक अमला अब हरकत में आया है और कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं:

शुरुआती धमाका

सबसे पहले दुर्ग में नशे की खेती पकड़ी गई, जिसमें बीजेपी नेता का नाम उजागर हुआ। इसके बाद बलरामपुर में दो जगहों पर अफीम की जब्ती हुई।

गिरफ्तारियां

भाजपा नेता विनायक ताम्रकार, विकास विश्नोई, मनीष ठाकुर समेत कई तस्कर सलाखों के पीछे हैं।

सिस्टम पर गाज

दुर्ग में कृषि विस्तार अधिकारी और बलरामपुर में संदिग्ध पटवारियों को नोटिस जारी कर ट्रांसफर और निलंबन की कार्रवाई की गई है।

सीएम का कड़ा रुख

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 'जीरो टॉलरेंस' का ऐलान करते हुए सभी कलेक्टरों को 15 दिनों के भीतर प्रदेशव्यापी सर्वे और सीमांकन की रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है।

विवरण,आंकड़े/कीमत

जब्त अफीम के पौधे (दुर्ग),14 लाख
(कीमत ₹7.88 करोड़)
इंटरस्टेट नेटवर्क,चतरा (झारखंड) से दिल्ली-पंजाब तक

अंतरराष्ट्रीय कीमत (हेरोइन)*
₹2 करोड़ प्रति किलो
निरीक्षण विफलता,5 महीने तक प्रशासन को भनक नहीं लगी

सियासी संग्राम: विपक्ष हमलावर, सरकार का 'जीरो टॉलरेंस'

विधानसभा में अफीम की गूंज ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे 'अफीम स्टार्टअप' करार देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर सर्वे करने को कहा है। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को 15 दिन में सर्वे रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। भाजपा नेता विनायक ताम्रकार की गिरफ्तारी कर सरकार ने संदेश दिया है कि अपराध में 'कैडर' की ढाल काम नहीं आएगी।

बिना मान्यता स्कूलों में एडमिशन के खेल पर हाईकोर्ट सख्त

शिक्षा सचिव से मांगा 'पर्सनल एफिडेविट', पांच स्कूलों को नोटिस जारी

कोर्ट ने पूछा- अदालती आदेशों के बावजूद बिना मान्यता कैसे छप रहे विज्ञापन? 24 मार्च को अगली सुनवाई

शहर सत्ता/बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों और उनके द्वारा दिए जा रहे प्रवेश विज्ञापनों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा (Personal Affidavit) दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना मान्यता के स्कूलों द्वारा एडमिशन का विज्ञापन देना अदालती आदेशों की खुली अवमानना है।

शिकायतों पर कार्रवाई न होने से कोर्ट नाराज

मामले की सुनवाई जनहित याचिका (WPPIL No. 22/2016) में इंटरवीनर विकास तिवारी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर हुई। कोर्ट को बताया गया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 5 फरवरी 2026 को ही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर बेंच ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

इन 5 स्कूलों को बनाया पक्षकार, जारी हुआ नोटिस

सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष एक पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन पेश किया गया, जिसमें सत्र 2026–27 के लिए उन स्कूलों में प्रवेश की जानकारी दी गई थी जिनकी आवश्यक मान्यता को लेकर सवाल खड़े हैं। कोर्ट ने कृष्णा पब्लिक स्कूल (तुलसी, रायपुर) सहित कृष्णा किड्स एकेडमी की चार अन्य शाखाओं को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वाली शाखाओं में शामिल हैं: शंकर नगर, न्यू राजेंद्र नगर, सुंदर नगर, शैलेंद्र नगर।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता के अनुसार, कई निजी स्कूल आवश्यक कानूनी मान्यता के बिना ही धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। हाईकोर्ट के पूर्व के कड़े आदेशों के बावजूद ये स्कूल न केवल चल रहे हैं, बल्कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगली सुनवाई 24 मार्च को: कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की है। उस दिन शिक्षा सचिव को यह बताना होगा कि अब तक विभाग ने इन अवैध संस्थानों पर ताला क्यों नहीं लगाया और विज्ञापन देने वालों पर क्या कार्रवाई की गई।

भाठागांव में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर कार्रवाई के बाद दोबारा बनाई थी सड़क

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी के भाठागांव इलाके में अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन ने रविवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। 'शंकरा विहार' नाम से काटी जा रही अवैध कॉलोनी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मुरुम की सड़कों को उखाड़ दिया। खास बात यह है कि महज 6 दिन पहले हुई कार्रवाई के बावजूद आरोपियों ने दोबारा सड़क बना ली थी, जिसे प्रशासन ने रविवार सुबह फिर से ध्वस्त कर दिया। नगर निगम जोन-6 के कमिश्नर हितेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने 9 मार्च को पहली बार इस स्थल पर दबिश दी थी। तब करीब एक एकड़ में फैले अवैध निर्माण और रास्तों को तोड़ा गया था। प्रशासन की चेतावनी को दरकिनार कर आरोपियों ने दोबारा वहां सड़कें तैयार कर लीं। शिकायत मिलते ही रविवार 15 मार्च की सुबह निगम और राजस्व की संयुक्त टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और निर्माण को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। जांच में सामने आया है कि हल्का नंबर 105/60 के अंतर्गत खसरा नंबर 940/1, 940/2 से लेकर 944/2 तक की लगभग 5 एकड़ जमीन पर बिना किसी वैध अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम से ले-आउट पास कराए बिना ही यहां ऊंचे दामों पर जमीन बेचने की तैयारी थी।

इन पर दर्ज होगी एफआईआर

नायब तहसीलदार प्रवीण परमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भरत भूषण सिंह और कौशल सोनकर द्वारा अवैध प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत मिली थी। बार-बार नियमों के उल्लंघन को देखते हुए अब केवल तोड़फोड़ तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी।

टैक्स नहीं चुकाया तो सार्वजनिक होगी 100 बड़े बकायादारों की सूची, निगम करेगा कुर्की

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी में संपत्तिकर की वसूली को लेकर नगर पालिक निगम ने अब 'नेम एंड शेम' की रणनीति अपनाई है। निगम प्रशासन ने शहर के सभी 10 जोनों से 10-10 सबसे बड़े बकायादारों की लिस्ट तैयार की है। यदि इन रसूखदारों ने जल्द टैक्स जमा नहीं किया, तो निगम इन 100 बड़े डिफॉल्टरों के नाम और विवरण सार्वजनिक करेगा। इसके साथ ही लंबे समय से टैक्स दबाए बैठे लोगों के खिलाफ कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

छुट्टी के दिनों में भी जमा होगा टैक्स

राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने और नागरिकों की सुविधा के लिए निगम ने बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च 2026 तक रायपुर के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग शनिवार और रविवार (अवकाश के दिनों) को भी सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार इन छुट्टियों में भी काउंटर पर जाकर कर का भुगतान कर सकते हैं।

17 प्रतिशत एक्स्ट्रा चार्ज का खतरा

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो करदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना संपत्तिकर जमा नहीं करेंगे, उनसे नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार (Surcharge) वसूला जाएगा। भारी-भरकम जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए निगम ने करदाताओं से तत्काल भुगतान की अपील की है।

घर बैठे भुगतान की भी सुविधा

नगर निगम ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन विकल्प भी खुले रखे हैं:

मोर रायपुर ऐप: नागरिक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सीधे भुगतान कर सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्टल: निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी संपत्तिकर जमा किया जा सकता है।

मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति में देरी पर UPSC सख्त

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ पुलिस फोर्स (DGP) की स्थाई नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव विकासशील को कड़ा पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है कि राज्य में अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

यूपीएससी ने जताई कड़ी नाराजगी

आयोग के अवर सचिव दीपक शॉ द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि UPSC ने 13 मई 2025 को ही योग्य अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेज दिया था। नियमानुसार, सरकार को इस पैनल में से किसी एक अधिकारी को तत्काल पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करना था। पत्र में सवाल उठाया गया है कि 3 जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ? आयोग ने सरकार से इस विलंब का ठोस कारण बताने को कहा है।

'प्रभारी' व्यवस्था पर फंसा पेच

मामले की जड़ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों का स्वरूप है। सरकार ने यूपीएससी के पैनल के आधार पर अरुण देव गौतम को डीजीपी तो नियुक्त किया, लेकिन उन्हें 'पूर्णकालिक' प्रभार देने के बजाय 'प्रभारी' (In-charge) डीजीपी बना दिया। 'प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार' मामले में शीर्ष अदालत ने साफ कहा था कि राज्यों में 'कार्यवाहक' या 'प्रभारी' डीजीपी की परंपरा नहीं चलेगी। डीजीपी की नियुक्ति स्थाई और न्यूनतम दो साल के कार्यकाल के लिए होनी चाहिए।

अवमानना की लटकी तलवार

हाल ही में 5 फरवरी 2026 को 'टी धंगोपल राव बनाम यूपीएससी' मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए चार निर्देश दिए थे। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि नियुक्ति में देरी होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब अगली सुनवाई से पहले छत्तीसगढ़ सरकार के पास दो ही विकल्प बचे हैं अरुण देव गौतम की नियुक्ति को तत्काल पूर्णकालिक किया जाए। आयोग और अदालत को ऐसा ठोस कारण दिया जाए जो कानूनी रूप से मान्य हो।

रायपुर एयरपोर्ट पर फर्जी आधार से सफर की कोशिश, इंदौर का फोटोग्राफर गिरफ्तार

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से फर्जी पहचान पत्र के आधार पर हवाई यात्रा करने की कोशिश कर रहे एक युवक को पकड़ा गया है। आरोपी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट और आधार कार्ड में अपनी फोटो लगाकर रायपुर से इंदौर जाने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, घटना 12 मार्च 2026 की है। इंदौर निवासी आरोपी कुलदीप सिंघल रायपुर से इंदौर जाने वाली फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचा था। उसने एंट्री गेट और सुरक्षा जांच के दौरान स्नेहल राजू भाई पटेल के नाम से जारी एयर टिकट और आधार कार्ड दिखाया। सुरक्षा कर्मियों को आधार कार्ड की बनावट और फोटो पर संदेह हुआ। गहनता से जांच करने पर पता चला कि आधार कार्ड मूल रूप से स्नेहल पटेल का है, लेकिन उस पर फोटो कुलदीप ने अपनी लगा रखी थी। माना सीएसपी लंबोदर पटेल ने बताया कि आरोपी कुलदीप सिंघल पेशे से फोटोग्राफर है। उसने अपने किसी परिचित (स्नेहल राजू भाई पटेल) के आधार कार्ड का उपयोग किया और फोटो एडिटिंग के जरिए उसमें अपनी तस्वीर चस्पा कर कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार किया। वह इसी फर्जी आईडी के जरिए स्नेहल के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करना चाहता था। एयरपोर्ट सुरक्षा बल ने आरोपी को हिरासत में लेकर माना थाना पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

साप्ताहिक शहर सत्ता

हाथी संरक्षण पर सवाल, छह साल में 70 हाथियों की मौत

केंद्र-राज्य की चल रही आधा दर्जन योजनाएं

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आधा दर्जन योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। पिछले छह वर्षों में राज्य में 70 हाथियों की मौत हो चुकी है। सबसे चिंताजनक स्थिति वर्ष 2025 में रही, जब अकेले 16 हाथियों की मौत दर्ज की गई। इनमें 7 शावक हाथियों की मौत नदी-तालाबों में डूबने से होना बताया गया है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हाथियों की मौत के अधिकतर मामले खेतों की सुरक्षा के लिए लगाए गए करंट वाले तारों की चपेट में आने से जुड़े हैं। वर्ष 2020 में 3, 2021 में 4, 2022 में 9 जबकि 2023 से जनवरी 2026 के बीच 14 हाथियों की करंट लगने से मौत हुई।

इसे मानव-हाथी संघर्ष का नतीजा माना जाता है। विभाग इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने और करंट वाले तार लगाने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की कार्रवाई करता है। हालांकि दूसरी तरफ तालाबों और नदियों में डूबने से हो रही मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस योजना नजर नहीं आती। वर्ष 2025 में ही सात शावक हाथियों की मौत तालाबों और दलदली जलाशयों में डूबने से हुई है। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में बार-बार हाथियों के डूबने की घटनाएं हो रही हैं, तो वहां के जलाशयों और दलदली क्षेत्रों को चिन्हित कर सुरक्षा घेरा बनाने के साथ निगरानी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

रायगढ़ वन मंडल में सबसे ज्यादा मौतें सबसे ज्यादा हाथियों की मौत रायगढ़ वन मंडल में दर्ज की गई है। यहां सात में से पांच शावक हाथियों की मौत तालाबों में डूबने या दलदल में फंसने से हुई है। क्षेत्र में हाथियों की लगातार आवाजाही के बावजूद जल स्रोतों के आसपास सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से जोखिम बना हुआ है। प्रदेश में हाथियों की संख्या और उनके मूवमेंट को देखते हुए सरकार ने कई संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य हाथियों की निगरानी, कॉरिडोर संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष को कम करना है। इसके बावजूद लगातार हो रही मौतें यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या संरक्षण योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, या जमीनी स्तर पर उनकी निगरानी और क्रियान्वयन में गंभीर कमी है।

छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में हल्की बारिश की संभावना

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने से गर्मी की शुरुआत हो गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने सेंट्रल और साउथ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश का तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान 39.6°C बिलासपुर में दर्ज किया गया। वही सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ है। हालांकि, अगले 24 घंटों में पारा 4°C तक गिर सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अगले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम का रुख बदलेगा। इससे तेज गर्मी पड़ रही इलाकों में राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज (15 मार्च) दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, अगले दो दिनों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जिसमें हवाओं की रफ्तार 50-60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण आंतरिक ओडिशा तक एक 'ट्रफ' (कम दबाव वाली रेखा) बनी हुई है, जो छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है। यह सिस्टम समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह रेखा नमी को खींचती है।

Nini TV पर छत्तीसगढ़ी भाषा की एंट्री, रायपुर में लॉन्च की घोषणा

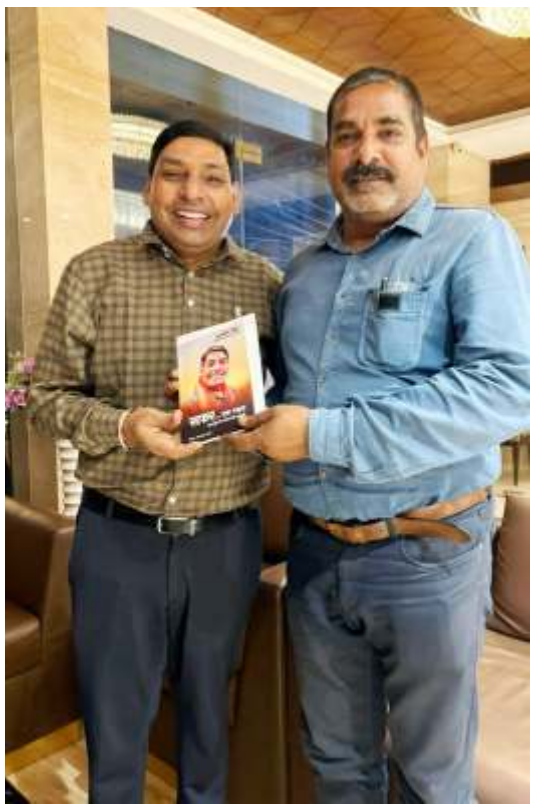

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर। डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका Nini TV अब क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। Nini TV ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ी भाषा को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने की घोषणा की है। इस अवसर पर आज रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चैनल की नेशनल मार्केट हेड श्रद्धा सिंह ने बताया कि Nini TV पहले से ही तमिल, तेलुगु, मलयालम, राजस्थानी और गुजराती जैसी कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करा रहा है। अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ी फिल्में और मनोरंजन सामग्री को भी अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि Nini TV के इस नए कदम से छत्तीसगढ़ी सिनेमा और स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा डिजिटल मंच मिलेगा। साथ ही दर्शक अब Nini TV पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी देख सकेंगे, जिससे इन फिल्मों की पहुंच देश-विदेश के दर्शकों तक और अधिक बढ़ेगी। कंपनी का मानना है कि यह पहल छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति और सिनेमा को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और क्षेत्रीय कंटेंट को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी।

जनगणना 2027 की तैयारी शुरू

निगम जोन 4 में सर्वे प्रारंभ, रविशंकर शुक्ल वार्ड से शुरुआत

शहर सत्ता/रायपुर। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 4 में सर्वे कार्य की शुरुआत कर दी गई है। जनगणना निदेशालय के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के मार्गदर्शन में जोन 4 की टीम ने पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर में जनगणना सर्वे का कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी के निर्देशन में कार्यपालन अभियंता शेखर सिंह, सहायक अभियंता दीपक देवांगन सहित जोन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ओर से क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत मकानों का विवरण और आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है।

बाकी वार्डों में जल्द शुरू होगा सर्वे और मकानों की नंबरिंग

नगर निगम प्रशासन के अनुसार जनगणना निदेशालय के निर्देशानुसार जोन 4 के साथ-साथ रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्य वार्डों में भी जल्द ही सर्वे और मकानों की नंबरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की संबंधित जोन टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जनगणना 2027 की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।

पूर्व सीएम बघेल ने की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

पोटा केबिन की 3 छात्राएं गर्भवती, दो नाबालिग; प्रशासन पर उठे सवाल

शहर सत्ता/बीजापुर। जिले के गंगालूर क्षेत्र स्थित पोटा केबिन आवासीय संस्था (RMSA) में रहने वाली तीन आदिवासी छात्राओं के गर्भवती होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इनमें से दो छात्राएं कक्षा 12वीं और एक 11वीं की छात्रा है। बताया जा रहा है कि इनमें से दो छात्राएं नाबालिग हैं और तीनों ही करीब 5 माह की गर्भवती हैं। इस खुलासे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और आवासीय विद्यालयों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

5 महीने से गायब थीं छात्राएं, परीक्षा देने पहुंचीं तो खुला राज

जानकारी के अनुसार, छात्राओं के गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद उन्हें करीब 5 माह पहले ही संस्था से हटा दिया गया था। इसके बाद से वे नियमित स्कूल नहीं आ रही थीं। हालांकि, शनिवार को कक्षा 12वीं की दो छात्राएं अपनी अंतिम परीक्षा देने पहुंचीं, जिसके बाद यह पूरा मामला सार्वजनिक हुआ।

जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा प्रबंधन

इस गंभीर लापरवाही पर पोटा केबिन की वर्तमान अधीक्षिका का कहना है कि यह घटना उनके कार्यकाल की नहीं है और छात्राएं लंबे समय से संस्था से अनुपस्थित थीं। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) लखनलाल धनेलिया का तर्क है कि छात्राएं अपने घर से आना-जाना करती थीं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक गलियारों में उबाल

इस घटना को लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'X' पर पोस्ट कर भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि सरकारी अमला मामले को रफा-दफा करने में जुटा है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार के 'सुशासन' के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आश्रमों और स्कूलों में पढ़ने वाली आदिवासी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नीना रावतिया उद्दे जिला पंचायत सदस्य ने प्रबंधन और स्थानीय अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

भारतीय रसोईघर तक आई ईरान-इजरायल युद्ध की आंच

दुनिया भर में युद्ध सैन्य मोर्चों पर लड़े जाते रहे हैं, लेकिन उसकी आंच में आम लोग झुलसते हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद इस युद्ध का दायरा जिस स्वरूप में फैला है, उसका असर अब आशंका के अनुरूप सामने आना शुरू हो चुका है। समस्या यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश आमतौर पर हर समय इतनी पूर्व-सावधानी नहीं बरतते हैं कि युद्ध से उपजी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपायों को लेकर अपनी ओर से अगले कई महीनों के लिए पूरी तैयारी रखें। कई बार अचानक पैदा होने वाले हालात में पहले आपूर्ति का मोर्चा बाधित होता है।

उसके बाद आम लोगों के जीवन-बसर के लिए अनिवार्य चीजों की कमी शुरू हो जाती है और फिर उसका असर बाहर भी दिखने लगता है, जिसमें लोगों के बीच रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की समस्या को लेकर चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के दस दिन बाद कई देशों में लगभग यही स्थिति बन रही है। जहां तक भारत का सवाल है, तो जब से ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते को रोका है, तब से तेल टैंकरों की आवाजाही और गैस की आपूर्ति भी व्यापक रूप से बाधित हुई है। इसके अलावा, ईरान ने जवाबी हमले के तौर पर जिस तरह खाड़ी के कई देशों के तेल रिफाइनरियों पर हमले किए, उसके बाद कच्चे तेल का संकट ज्यादा गहरा गया है। हालांकि होर्मुज मार्ग पर ईरान के रुख के बाद यह साफ हो गया था कि अगर यह युद्ध थोड़ा लंबा खिंचा, तो दुनिया के कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। तेल और गैस के अभाव की वजह से न सिर्फ आम जनजीवन में अफरा-तफरी पैदा होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट खड़ा होगा। इसी क्रम में भारत में अब यह साफ दिखने लगा है कि अगर सरकार की ओर से जल्दी ही कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति जटिल हो सकती है। दरअसल, युद्ध की आंच अब भारत में रसोईघरों और व्यापार तक पहुंचनी शुरू हो गई है। एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी यानी तरल पेट्रोलियम गैस के मामले में भारत आमतौर पर आयात पर निर्भर रहा है। यही वजह है कि होर्मुज समुद्री रास्ते से तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित होने के बाद भारत में अब एलपीजी की किल्लत का खतरा मंडराने लगा है और कई राज्यों में रेस्तरां तथा होटलों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में मुश्किल शुरू हो गई है।

साथ ही बाजार में खाने-पीने की चीजों से लेकर अन्य सामान की कीमतों में इजाफे की रफ्तार तेज हो गई है। असली समस्या रसोई गैस और अन्य सामान की आपूर्ति है, जिसमें भारी कमी की वजह से लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन रहा है। हालत यह है कि आने वाले दिनों में संकट गहराने की आशंका से ज्यादातर लोग एहतियातन एलपीजी सहित अन्य सामान लेने के लिए कतारों में खड़े दिखने लगे हैं।

एक ओर, जरूरत से ज्यादा खरीदारी और दूसरी ओर कारोबारियों की अवैध जमाखोरी या भंडारण की वजह से कालाबाजारी और महंगाई जैसे संकट के मद्देनजर सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना पड़ा है। मगर यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि रसोई गैस या परिवहन इस हद तक नियंत्रित न हों कि इससे रोजमर्रा की अनिवार्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि घबराहट में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए करीब 2.5 दिन का सामान्य आपूर्ति चक्र बरकरार है।

महिलाओं की मेहनत को समझना जरूरी

मोनिका शर्मा

कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने भी कहा था कि गृहिणी का काम वेतन घर लाने वाली महिला से कम नहीं होता। महिलाएं कामकाजी हों या गृहिणी, उनके श्रम का सम्मान उनके अस्तित्व की सहज स्वीकार्यता से जुड़ा है। हाल के वर्षों में कामकाजी स्त्रियों की उपस्थिति और आर्थिक भूमिका की स्वीकार्यता बढ़ी है। उनकी समस्याओं को समझने की सोच को बल मिला है। वहीं गृहिणियों के श्रम की अनदेखी से जुड़ी पारंपरिक सोच आज भी कायम है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई न्यायिक निर्णयों में घरेलू महिलाओं की भूमिका को समझने और सम्मान देने की बात कही गई।

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की कि गृहिणी को निष्क्रिय मानना घरेलू योगदान की गलत समझ को दर्शाता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि घरेलू संबंधों में पत्नी के योगदान के आर्थिक मूल्य को कानून में मान्यता दी जानी चाहिए। वर्ष 2012 में हुए विवाह से जुड़े मामले में पत्नी का आरोप था कि 2020 में पति ने उसे और नाबालिग बेटे को छोड़ दिया। निचली अदालत ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि पत्नी शिक्षित और सक्षम है, लेकिन उसने नौकरी नहीं की। मगर इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दो अलग बातें हैं। साथ ही भरण-पोषण के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह भी जोड़ा कि 'गृहिणी' या 'होममेकर' का श्रम कमाने वाले जीवनसाथी को प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है, इसलिए उसकी बेरोजगारी को आलस्य के बराबर मानना अन्यायपूर्ण है। ये टिप्पणियां स्त्री जीवन के उस आधारभूत पक्ष को संबोधित करती हैं, जिसकी अनदेखी की गई। जबकि स्त्रियों की इस भागीदारी में शारीरिक-मानसिक श्रम ही नहीं, भावनात्मक मोर्चे पर की गई मशक्कत भी होती है। बच्चों के पालन-पोषण से लेकर बुजुर्गों की संभाल तक संवेदना और संयम का यह परिश्रम हमारी पारिवारिक व्यवस्था को थामे हुए है। गृहिणी के रूप में अपने दायित्वों को संभालने वाली एक पूरी पीढ़ी आज की कामकाजी बहू-बेटियों के जीवन की बुनियाद बनाने वाली रही हैं।

वैवाहिक जीवन में भी घरेलू जिम्मेदारियां उठाने वाली महिलाएं जीवनसाथी का जीवन आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विचारणीय है कि मौद्रिक मूल्य न आंके जाने की वजह से महिलाओं की भूमिका के प्रति भेदभाव होता आया है। अपने घर की खेती-किसानी में हाथ बंटाने वाली महिला कृषक हो या सामाजिक-पारिवारिक रिश्तों को सहेजने में जीवन खपा देने वाली आम स्त्रियां, उनके योगदान की उपेक्षा का रवैया देश के हर हिस्से में रहा है। ऐसे में अदालत की यह टिप्पणी अहम हो जाती है कि कानून को केवल आय को ही नहीं, बल्कि विवाह के दौरान घर और पारिवारिक संबंधों में पत्नी के घरेलू श्रम के योगदान के आर्थिक मूल्य को भी मान्यता देनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल और परिवार के समर्थन का भी आर्थिक मूल्य है, भले ही वह आयकर या बैंक विवरण में दर्ज न हो। इसीलिए कानून यह सुनिश्चित करे कि परिवार निर्माण में समय और श्रम का निवेश करने वाला जीवनसाथी असहाय न रह जाए। विडंबना है कि स्त्रियों की इस श्रमशील भूमिका के प्रति सम्मान का भाव आज भी नदारद है। यहां तक कि उनके अस्तित्व को ही नकार देने का भाव दिखता है। कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने भी कहा था कि गृहिणी का काम वेतन घर लाने वाली महिला से कम नहीं होता। परिवार में भले ही उसके योगदान का मौद्रिक आकलन नहीं किया जा सकता, पर अपनों की देखभाल करने वाली इस भूमिका का विशेष महत्त्व है।

गौरतलब है कि 2006 में उत्तराखंड में हुई एक दुर्घटना में महिला की मौत हो गई थी। महिला जिस वाहन से यात्रा कर रही थी, उसका बीमा न होने की वजह से न्यायाधिकरण ने महिला के परिवार को ढाई लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया था। दुखद पक्ष यह रहा कि महिला को मिलने वाली बीमा राशि को न्यायाधिकरण ने कम आंका, क्योंकि महिला गृहिणी थी। इसलिए मुआवजा जीवन प्रत्याशा और न्यूनतम अनुमानित आय पर तय किया गया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा भी केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को एक सड़क हादसे में पीड़िता को इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार करने पर फटकार लगाई जा चुकी है कि पीड़िता एक गृहिणी है। गृहिणी होने की वजह मुआवजे का पात्र नहीं माने जाने के तर्क को अदालत ने अपमानजनक और समझ के परे बताते हुए कहा था कि हादसे के लिए मुआवजा एक गृहिणी और कामकाजी महिला के लिए समान होना चाहिए। सशक्त और सजग स्त्रियों का समाज बनाने वाले दावों और वादों के बीच घर-परिवार में स्त्री के परिश्रम की अनदेखी का बर्ताव दुखद है। जबकि गृहिणी या घर को घर बनाने वाली स्त्री की भागदौड़ से ही स्वजनों-परिजनों के जीवन की गति जुड़ी है। उनसे मिली देखभाल नई पीढ़ी को सपने साधने का धरातल देती है। उनकी मौजूदगी से वरिष्ठजनों को सुरक्षा-संभाल का भरोसा मिलता है।

बावजूद इसके आर्थिक उपार्जन का आकलन करने वाला समाज यह समझने का प्रयास नहीं करता कि यह भागीदारी अनमोल है। अफसोस कि सरकारी नीतियों और योजनाओं में भी गृहिणियों के लिए कहीं कोई विशेष प्रावधान नजर नहीं आता। जबकि वेतन चुकाकर न तो ऐसी जिम्मेदारियां किसी को दी जा सकती है और न ही कोई आत्मीय भाव संग ऐसे दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2021 की रपट बताती है कि विश्व में महिलाएं अवैतनिक घरेलू कार्यों के लिए कुल घंटों का छिहत्तर फीसद समय देती हैं। एशियाई देशों में यह आंकड़ा अस्सी फीसद से भी ज्यादा है। जरूरी है कि गृहिणियों को दूसरों पर निर्भर व्यक्तित्व के रूप में देखने के बजाय उनके श्रम के सम्मान का भाव आए। घर तक सिमटी जिंदगी जी रही महिलाओं को समझने का परिवेश बनाया जाए। उनकी भूमिका के प्रति उपेक्षा का व्यवहार उनका मनोबल तोड़ता है। ऐसे में अपनों की भावनात्मक समस्याओं को समझने वाली घरेलू स्त्रियों को भी समाज और परिवार का संबल मिले। यह भी पढ़ें: नौकरी तो मिल रही है, पर क्या वह 'क्वालिटी' वाली है? नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली सेवा क्षेत्र की पोल!

अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनस्पति और वन उत्पाद और खनन। दूसरा क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इसमें विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य और बिजली उत्पादन जैसी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है

चिंतनः दूसरों का भला चाहने वाले का होता है भला

एक लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां काटता और गांव के बाजार में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। बहुत परेशानियों में उसका जीवन चल रहा था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे के गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। संत के दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर-दूर से गांव पहुंच रहे थे। गरीब लकड़हारा भी संत से मिलने पहुंच गया। मौका मिलते ही गरीब व्यक्ति ने अपनी परेशानियां संत को बता दीं। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? संत ने उससे कहा कि ठीक हैं भगवान से प्रार्थना करूंगा।

कुछ दिन बाद लकड़हार संत के पास फिर से पहुंचा। संत ने उससे कहा कि भाई तुम्हारी किस्मत सिर्फ पांच बोरी अनाज ही है। इसीलिए भगवान तुम्हें थोड़ा-थोड़ा अन्न दे रहा है, ताकि तुम्हें जीवनभर खाना मिलता रहे। संत की बात सुनकर लकड़हार अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद वह फिर से संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी आप भगवान से कहो कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दे। कम से कम एक दिन मैं भरपेट भोजन करना चाहता हूं। संत ने कहा कि ठीक हैं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा।

अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर पांच बोरी अनाज पहुंच गई। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसीलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया है। उसने बहुत सारा खाना बनाया खुद खाया और गांव के गरीब लोगों को बांट दिया। सभी ने उसे दुआएं दीं। अगले दिन उसके घर फिर से पांच बोरी अनाज आ गया। उसने फिर ऐसा ही किया, खुद खाया और दूसरों को खाना खिला दिया।

काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों की खिला दिया तो तुम्हारे इस नेक काम से भगवान बहुत प्रसन्न हैं। इसीलि वे तुम्हें अन्य जरूरतमंद लोगों की किस्मत का अनाज भी दे रहे हैं। ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात गरीब व्यक्ति को समझ आ गई। इसके बाद उसने दूसरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखा।

साप्ताहिक शहर सत्ता

दो चरणों में होगा बंगाल में चुनाव

बंगाल में 23 व 29 अप्रैल व असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होगा मतदान

निर्वाचन आयोग (ECI) ने 15 मार्च को पांच राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) के चुनावों का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है. दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे.

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होगी वोटिंग

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग होगी, जबकि पिछली बार वहां 8 चरणों में मतदान हुआ था. वहीं, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में वोट डाले जाएंगे.

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में होगी वोटिंग?

असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा. जबकि पश्चिम बंगाल में दो फेज में चुनाव होगा. पहले चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा.

कब आएंगे चुनाव के नतीजे?

पांचों राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा. चुनाव का शेड्यूल जारी हो जाने के बाद इन राज्यों में आचार संहिता भी लग जाएगी.

पांचों राज्यों में कुल 17.4 करोड़ वोटर्स

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पांचों राज्यों-केंद्रशासित प्रदेश में कुल 17.4 करोड़ मतदाता हैं. जबकि यहां सीटों की कुल संख्या 824 है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव को लेकर कहा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इसे मतदान केंद्र के बाहर ही रखना होगा. वोट डालने के बाद मतदाता अपना मोबाइल वापस ले सकेंगे.वहीं इन सभी 5 राज्यों में पिछली बार चुनाव की तारीखों का ऐलान 26 फरवरी 2021 को किया गया था. तब पश्चिम बंगाल में 8 फेज में वोटिंग हुई थी. असम में 3 चरणों में मतदान हुआ था जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में वोट डाले गए थे. इन पांचों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है.

हर दो घंटे में अपलोड होगा मतदान प्रतिशत

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे. यहां 25 लाख चुनाव अधिकारियों की तैनाती की जाएगी. उन्होंने बताया कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या 750-900 है. उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर तैनात पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत अपलोड करेंगे और चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद मतदान के आंकड़े अपलोड किए जाएंगे.

इजरायली PMO ने नेतन्याहू की मौत की खबरों को किया खारिज

सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू ठीक हैं. अनादोलू एजेंसी के एक संवाददाता ने पूछा कि क्या उनके पास सोशल मीडिया पर फैल रही उन अफवाहों पर कोई बयान है कि नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है. इस पर PMO ने कहा कि ये फर्जी खबरें हैं.नेतन्याहू ने शुक्रवार को एक्स पर अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो साझा किया. वीडियो में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां देखने का दावा किया, जिससे ये अफवाह फैल गई कि ये AI वीडियो था.

वीडियो में 0:35 पर जब नेतन्याहू अपने हाथ उठाते हैं तो छोटी उंगली के बगल में अतिरिक्त मांस दिखाई देता है, जिसे कई लोगों ने छठी उंगली बताया जो एक क्लासिक एआई फिंगर ग्लिच है. अमेरिकी टिप्पणीकार कैंडेंस ओवेन्स ने उनके उपनाम से संबोधित करते हुए पूछा, 'बिबी कहां हैं?' उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'इजरायली पीएम कार्यालय उनके फर्जी AI वीडियो क्यों जारी कर रहा है और फिर हटा रहा है और व्हाइट हाउस में इतनी दहशत क्यों फैली हुई है?'एक यूजर ने बैकग्राउंड में लगे पर्दों के हिलने को लेकर कहा कि दोनों इजरायली झंडे स्थिर दिख रहे हैं. ध्यान दीजिए कि ब्लैकआउट पर्दा पूरे वीडियो में एक ही पैटर्न में हिलता है, मानो लूप में चल रहा हो जबकि दोनों झंडे बिल्कुल नहीं हिलते. यह स्पष्ट रूप से AI का संकेत है।

ईरान युद्ध के बीच गुड न्यूज, दो भारतीय जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किया पार

यूएस-ईरान के बीच छिड़ी जंग के चलते खड़े हुए LPG संकट के बीच भारत के लिए गुडन्यूज सामने आई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के दो एलपीजी शिप शिवालिक और नंदा सुरक्षित निकल चुके हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की ओर से यह जानकारी दी गई है. भारत के नजरिए से इन दो एलपीजी वाहक जहाजों का सुरक्षित लौटना इसलिए भी अहम है, जब देश में गैस और तेल की दिक्कतें बढ़ रही हैं. शुक्रवार (13 मार्च) को ही ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने इसके संकेत दिए थे. उन्होंने कहा था, भारत को इस समय दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा. इसके बाद दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकल आए जो भारत की ओर बढ़ रहे हैं.

16-17 मार्च को पहुंचेंगे भारत

मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के चीफ सीक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में स्थित फारस की खाड़ी में भारतीय फ्लैग के 24 जहाज थे, जिनमें से दो एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक और नंदा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकले हैं. दोनों शिप भारत की ओर बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया, दोनों जहाजों पर करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है. यह मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पर 16 और 17 मार्च को आएंगे.'

'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 22 इंडियन शिप फंसी'

राजेश सिन्हा ने बताया, फारस की खाड़ी में भारत के 24 जहाज थे, जिनमें से दो शिवालिक और नंदा सुरक्षित निकल चुके हैं. अब यहां 22 जहाज बचे हैं, जिन पर 611 नाविक सवार हैं।

अब एक ही घर में PNG और LPG नहीं चलेंगे साथ-साथ, सरकार ने लगाई रोक

मिडिल ईस्ट वॉर के चलते देश में तेल की किल्लत देखने को मिल रही है. इसके अलावा एलपीजी गैस को लेकर भी यही हाल नजर आ रहा है. अब खबर है कि सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, कि जिनके घर पीएनजी गैस का कनेक्शन है, वह एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं रख सकेंगे. साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को इसे भरवाने पर भी रोक लगा दी गई है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक अहम फैसला सुनाया. इसमें संशोधित रूप से एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा है कि इस संशोधन के तहत सरकार तेल कंपनियों को भी ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन और रिफिल देने का मना किया गया है, जिनके पास पाइल वाली प्राकृतिक गैस कनेक्शन मौजूद है. इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जो पाइप वाली नेचुरल गैस का कनेक्शन रखता है, और जिसके पास घरेलू गैस का कनेक्शन भी है, वह घरेलू एलपीजी कनेक्शन अपने पास नहीं रखेगा. न ही किसी सरकारी तेल कंपनी, या उनके वितरकों और न ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लेगा. सरकार ने अपील की है कि वे रसोई गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर घबराहट में

न आएं. देश के पास इनका पर्याप्त भंडार है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके इलाके में पीएनजी की सुविधा है, तो उसके लिए भी अप्लाई करें. वहीं, सिलेंडर के लिए सरकार वेबसाइट पर अप्लाई करने का निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया गया है. इधर, सरकार एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।

कश्मीर के 101 छात्र ईरान से पहुंचेंगे भारत, 90 ने पार की अजरबैजान सीमा

ईरान से भारतीय मेडिकल छात्रों को निकालने का अभियान जारी है. जम्मू और कश्मीर के कई छात्रों सहित लगभग 101 छात्रों का पहला जत्था 15 मार्च को भारत पहुंचने की उम्मीद है. जानकारी के अनुसार पहला जत्था ईरान से होते हुए आर्मेनिया के येरेवन स्थित ज़्वार्टनोट्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 1:25 बजे रवाना होगा. छात्र भारत पहुंचने से पहले दुबई होते हुए यात्रा करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 90 छात्र पहले ही अजरबैजान में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि ईरान में फंसे भारतीय नागरिक निकासी मार्ग के तहत कई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की ओर जा रहे हैं. इस बीच अखिल भारतीय मेडिकल छात्र संघ (एआईएमएसए) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने कहा कि युद्धग्रस्त ईरान में फंसे सभी छात्रों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि इस्फ़हान और अराक के छात्र जो वर्तमान में अपने-अपने छात्रावासों में रह रहे हैं, उन्होंने एआईएमएसए सहित संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे उनकी चिंताओं को अधिकारियों के समक्ष उठाएं और उनके पुनर्वास में तेजी लाएं. उन्होंने कहा कि उनके पुनर्वास कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता के कारण उनमें चिंता बढ़ रही है।

ईरान के खिलाफ ट्रंप की अपील पर आया जवाब

क्या होर्मुज में युद्धपोत भेजेंगे चीन और ब्रिटेन?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने अन्य देशों से भी अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने जहाज भेजें. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है. हाल के तनाव के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ट्रंप की इस अपील के बाद चीन और ब्रिटेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि दोनों देशों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजेंगे या नहीं.

अमेरिका में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि चीन चाहता है कि दुश्मनी तुरंत खत्म हो और सभी पक्ष स्थिर और बिना रुकावट ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ चीन अपने संबंधों को मजबूत करते हुए तनाव कम करने और शांति बहाल करने की कोशिश करेगा. इसी तरह ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूके अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस इलाके में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रहा है.

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ क्या कहा?

इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि कई देश अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं.ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक खत्म हो चुकी है. हालांकि उन्होंने कहा कि फिर भी ड्रोन, माइन या छोटी दूरी की मिसाइलों से इस समुद्री रास्ते को खतरा हो सकता है. इसके अलावा ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि ईरान की योजना पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने और इजरायल को नष्ट करने की थी, लेकिन अब उसकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं.

आईपीएल में आखिरी बार खेलेंगे तीन दिग्गज खिलाड़ी

टूर्नामेंट के बाद ले सकते हैं संन्यास

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) को शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है. पहला मुकाबला पिछले साल की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी जैसे दिग्गजों को मैदान पर देखने के लिए फैंस उत्सुक हैं. धोनी जहां सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं तो वहीं रोहित और कोहली भी सिर्फ वनडे इंटरनेशनल और आईपीएल में ही खेलते हैं. यहां हम उन 4 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जिनके लिए आईपीएल 2026 बतौर प्लेयर आखिरी सीजन साबित हो सकता है.

एमएस धोनी (CSK)

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में हैं, जो अपनी कप्तानी में 5 बार सीएसके को चैंपियन बना चुके हैं. वह पहले सीजन से (2016 और 2017 को छोड़कर) चेन्नई टीम के लिए खेल रहे हैं, हालांकि वह अब कप्तान नहीं हैं लेकिन पिछले सीजन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बाद होने के बाद उन्हें कप्तानी संभालनी पड़ी. धोनी आईपीएल 2026 की तैयारियों में जुट गए हैं, जो उनका बतौर प्लेयर आखिरी सीजन हो सकता है. आईपीएल 2026 के लिए सीएसके ने संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया है, जिन्हें धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है. संजू हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे. धोनी के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 278 मैचों में 5439 रन बनाए हैं, इसमें 24 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं.

अजिंक्य रहाणे (KKR)

कोलकाता नाइट राइडर्स ने साफ किया है कि अजिंक्य रहाणे आईपीएल 2026 में कप्तान बने रहेंगे. हालांकि बतौर बल्लेबाज अगर ये सीजन रहाणे के लिए फ्लॉप रहा तो उनके लिए ये सीजन आखिरी साबित हो सकता है. 37 वर्षीय रहाणे को अगर केकेआर ने रिलीज कर दिया तो बहुत मुश्किल है कि कोई नई टीम उन्हें खरीदे. रहाणे ने आईपीएल में 198 मैचों में 5032 रन बनाए, जिसमें 33 अर्धशतक और 2 शतक जड़े हैं.

इशांत शर्मा (GT)

37 वर्षीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने आईपीएल में 117 मैचों में 96 विकेट लिए हैं. पिछले सीजन इशांत गुजरात टाइटंस में शामिल हुए थे, जिसमें वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने 7 मैचों में सिर्फ 4 विकेट लिए, इसमें उनका इकॉनमी 11.18 का था. वह आगामी सीजन में भी इसी टीम के लिए खेलेंगे, लेकिन अगर उनका प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है. यानी उनका आईपीएल करियर इस सीजन पर निर्भर करेगा.

ईरान वॉर के बीच स्टॉक मार्केट में हाहाकार

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. भारी बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 13 मार्च 2026 को बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. S&P BSE Sensex 1,470.50 अंक गिरकर 74,563.92 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि NSE Nifty 50 488.05 अंक लुढ़ककर 23,151.10 के स्तर पर आ गया. सबसे ज्यादा दबाव ऑटो और मेटल शेयरों पर देखने को मिला, क्योंकि सप्लाई सीमित होने और इनपुट लागत बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. मिडिल ईस्ट में तनाव 28 मार्च से बढ़ना शुरू हुआ और तब से भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है. 27 फरवरी को S&P BSE Sensex 81,287 के स्तर पर था, जो अब गिरकर करीब 74,500 के आसपास आ गया है. यानी इस दौरान बाजार में करीब 6,787 अंकों की गिरावट दर्ज की गई.9 मार्च को ईरान से जुड़े तनाव के कारण सेंसेक्स इंट्राडे में करीब 2,500 अंक तक गिर गया था और लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,424 के स्तर पर पहुंच गया था. वहीं NSE Nifty 50 भी करीब 750 अंक टूटकर 23,697 के स्तर पर आ गया था.

अमेरिकी टैरिफ का असर

इससे पहले 7 अप्रैल 2025 को अमेरिका द्वारा ऊंचे टैरिफ लगाए जाने के बाद भी बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी. उस दिन S&P BSE Sensex गिरकर 73,137.9 के स्तर तक पहुंच गया था. लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद भी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. उस समय सेंसेक्स करीब 5.74 प्रतिशत और NSE Nifty 50 लगभग 5.93 प्रतिशत तक गिर गया था. कुछ ही घंटों में निवेशकों के लगभग 31 लाख करोड़ रुपये डूब गए थे.

हिंडनबर्ग रिपोर्ट

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई थी, जिससे निवेशकों में घबराहट का माहौल बन गया था. 23 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के दौरान भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई थी. उस दिन S&P BSE Sensex 3,935 अंक यानी 13.15 प्रतिशत और NSE Nifty 50 1,135 अंक यानी 12.98 प्रतिशत गिर गया था. जनवरी से मार्च 2020 के बीच बाजार ने अपनी करीब 38 प्रतिशत वैल्यू खो दी थी.

मिडिल ईस्ट तनाव ने बिगाड़ा अंडे का फंडा

पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के खाद्य कारोबार पर भी दिखने लगा है. हाल के दिनों में देश में अंडों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि खाड़ी देशों को होने वाला अंडों का निर्यात प्रभावित हुआ है. दरअसल, क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण वहां की मांग और सप्लाई चेन दोनों पर असर पड़ा है. जिसका सीधा प्रभाव भारत के पोल्ट्री बाजार और अंडों के दाम पर दिखाई दे रहा है.देश के कई बाजारों में अंडों की कीमतों में हाल के दिनों में गिरावट देखी जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलूरु के थोक बाजार में अंडे की कीमत पहले करीब 7 रुपये प्रति पीस थी, जो घटकर लगभग 5 रुपये तक आ गई है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट में जोरदार उछाल

देश के रियल एस्टेट बाजार में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मेट्रो शहरों में बढ़ती कीमतों के बीच निवेशक और होमबायर्स तेजी से टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर रुख कर रहे हैं.प्रॉपटेक कंपनी स्क्वायर यार्ड्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के कारण आने वाले 2 से 4 वर्षों में इन शहरों में जमीन और प्लॉट की कीमतें 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं. आइए जानते हैं, रिपोर्ट के विषय में.....

इन शहरों में तेजी से बढ़ रही मांग

रिपोर्ट के अनुसार इंदौर, जयपुर, भोपाल, नागपुर, चंडीगढ़, मोहाली,लखनऊ, रायपुर, लुधियाना, पटना, रांची, जालंधर और उदयपुर जैसे शहरों में पिछले कुछ वर्षों में जमीन और प्लॉट की मांग तेजी से बढ़ी है.

फ्लैट और प्लॉट की कीमतों में बढ़ोतरी का रुझान

पिछले कुछ सालों में कई शहरों में रियल एस्टेट की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है. हालांकि प्लॉट के दाम फ्लैट की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़े हैं. उदाहरण के तौर पर, इंदौर में फ्लैट की कीमतों में लगभग 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. जबकि प्लॉट के दाम 85 से 100 फीसदी तक उछल गए हैं.जयपुर में भी फ्लैट की कीमतें 65 फीसदी तक उछली है, लेकिन प्लॉट की कीमतों में 75 से 90 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है.

Meta में बड़े स्तर पर जॉब कट की आशंका

टेक दुनिया की जानी मानी कंपनी Meta Platforms में एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की चर्चा तेज हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने कुल वर्कफोर्स का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा कम कर सकती है. जिससे करीब 16,000 कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ने की आशंका है. बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते खर्च को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है. साथ ही कंपनी भविष्य में ऐसी टीम तैयार करना चाहती है जो AI की मदद से ज्यादा प्रभावी और तेजी से काम कर सके. कॉरपोरेट फाइलिंग के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी में करीब 79,000 लोग काम कर रहे थे. ऐसे में अगर कंपनी अपने वर्कफोर्स में लगभग 20 फीसदी की कटौती करती है, तो करीब 16,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा हो सकता है.यदि यह योजना लागू होती है, तो इसे 2022–23 के दौरान की गई बड़े स्तर की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी माना जाएगा. फिलहाल यह कदम संभावित माना जा रहा है और अंतिम फैसला सामने आना बाकी है.

वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होने से पहले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी वित्तीय काम

31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होने से पहले टैक्सपेयर्स के लिए कुछ जरूरी वित्तीय काम पूरे करना अहम हो जाता है. क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है.ऐसे में 31 मार्च 2026 से पहले कुछ जरूरी कदम उठाकर लोग टैक्स बचा सकते हैं और पेनल्टी से भी बच सकते हैं. आइए जानते हैं, किन कामों को समय रहते निपटा लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर परेशानी न हो.....

निवेश से जुड़े दस्तावेज करें जमा

अगर किसी कर्मचारी ने साल की शुरुआत में टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग निवेश की जानकारी अपने नियोक्ता को दी थी, तो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले उनके प्रूफ जमा करना जरूरी होता है.आमतौर पर यह काम 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए. यदि कर्मचारी समय पर निवेश से जुड़े दस्तावेज नहीं देता है, तो कंपनी उसकी सैलरी से ज्यादा टीडीएस काट सकती है. जिससे आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन सकती है.

समय पर एडवांस टैक्स भरना जरूरी

जिन टैक्सपेयर्स की कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा बनती है, उनके लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है. इसके लिए अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 तय की गई है. अगर कोई व्यक्ति इस तय समय तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है, तो बाद में उसे अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए वित्त वर्ष खत्म होने से पहले इस जिम्मेदारी को पूरा करना जरूरी माना जाता है.

टैक्स बचत के लिए इन योजनाओं में कर सकते हैं निवेश

पुराने टैक्स सिस्टम का विकल्प चुनने वाले लोग कुछ खास बचत योजनाओं में पैसा लगाकर टैक्स में राहत पा सकते हैं. आयकर नियमों के तहत ऐसे निवेशों पर छूट मिलती है, जिनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसी स्कीमें शामिल हैं. इन योजनाओं में निवेश करने से टैक्स देनदारी कम हो सकती है. वहीं खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए हर साल तय न्यूनतम रकम जमा करना भी जरूरी होता है. वित्त वर्ष खत्म होने से पहले इन सब की जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए.

हेल्थ इंश्योरेंस पर भी मिलती है टैक्स में राहत

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरने पर टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80D के तहत छूट का लाभ मिलता है. इस प्रावधान के तहत व्यक्ति अपने और परिवार के लिए भरे गए प्रीमियम पर अधिकतम 25,000 रुपये तक की छूट पा सकता है. वहीं अगर बीमित व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है तो यह सीमा 50,000 रुपये तक हो जाती है।

विवादों के बीच यश दयाल ने चुपचाप कर ली शादी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल ने विवादों के बीच चुपचाप शादी कर ली है. यूपी के लिए खेलने वाले गेंदबाज पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते वह बीते कुछ वक्त से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं. इन आरोपों के चलते यश यूपी टी20 लीग 2025 में नहीं खेल सके थे. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन यानी IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं? इसी बीच उनकी शादी की खबर ने सबको हैरान कर दिया. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आरसीबी के तेज गेंदबाज ने शादी कर ली है. बताया गया का उनकी शादी 04 फरवरी को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुई थी. शादी को बहुत गुपचुप तरीके से किया गया था।

साप्ताहिक शहर सत्ता

विधायक रिकेश सेन की हत्या की साजिश पर सियासत

'पीली फाइल' की जांच न होने पर कांग्रेस ने घेरा, सुपेला थाने में सौंपा ज्ञापन

शहर सत्ता/भिलाई/दुर्ग। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की हत्या की कथित साजिश और रहस्यमयी 'पीली फाइल' का मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई या खुलाशा न किए जाने पर अब विपक्ष (कांग्रेस) ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सुपेला थाने पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

क्या है 'पीली फाइल' का रहस्य?

पूरा विवाद महिला दिवस के दिन शुरू हुआ, जब विधायक रिकेश सेन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी जान को खतरा बताया था। उन्होंने भाजपा के ही पूर्व पार्षद जयप्रकाश (जेपी) यादव का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें यादव एक पीले रंग की फाइल थामे नजर आ रहे थे। दावा किया गया कि इस फाइल में उन सफेदपोशों और साजिशकर्ताओं के नाम दर्ज हैं, जो विधायक को फर्जी दुष्कर्म केस में फंसाने या उनकी हत्या की साजिश रच रहे थे।

जहर देने और एक्सीडेंट की रची गई थी योजना!

विधायक रिकेश सेन ने सनसनीखेज आरोप लगाया था कि उन्हें अकेले घर से बाहर न निकलने और किसी के यहां भोजन न करने की चेतावनी दी गई थी। साजिश के तहत उन्हें:

- जन्मदिन के बहाने केक में जहर देकर मारने,
- भोजन पर बुलाकर विषाक्त पदार्थ खिलाने,
- या फिर हत्या को सड़क दुर्घटना (एक्सीडेंट) का रूप देने की योजना बनाई गई थी।

कांग्रेस ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

भिलाई कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा, "यह बेहद चिंताजनक है कि सत्ता पक्ष का विधायक खुद को असुरक्षित बता रहा है और पुलिस एक हफ्ते बाद भी साजिशकर्ताओं के नाम उजागर नहीं कर पाई है। हम मांग करते हैं कि पीली फाइल के सच को सामने लाया जाए और विधायक को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।" गौरतलब है कि इस मुद्दे को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में भी उठाया था।

ठगी के आरोपी जेपी यादव का यू-टर्न

इस मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव का है। 11 फरवरी को यादव पर नौकरी के नाम पर 16 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज हुआ था। शुरुआत में उन्होंने इसके लिए विधायक रिकेश सेन को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अचानक उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर विधायक के पक्ष में खड़े होने और साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया। शहर में यह चर्चा आम है कि यदि साजिशकर्ताओं के नाम फाइल में मौजूद हैं, तो पुलिस अब तक जयप्रकाश यादव से वह फाइल हासिल कर जांच आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई? क्या इसमें कुछ प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं?

कथावाचक बोले- ' मंत्री ने 15 लाख नहीं दिए, मांगने पर धक्के मिले, विधानसभा के बाहर कर लूंगा आत्मदाह'

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध कथावाचक द्वारा कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल पर लगाए गए सनसनीखेज आरोपों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। डॉ. रामानुरागी महाराज नामक कथावाचक ने एक भावुक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि मंत्री ने उनसे श्रीमद्भागवत कथा तो कराई, लेकिन तय की गई 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया। इतना ही नहीं, कथावाचक ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे विधानसभा के गेट नंबर-3 के बाहर आत्मदाह कर लेंगे।सोशल मीडिया पर वायरल 1 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में डॉ. रामानुरागी महाराज ने व्यथित होकर कहा कि उन्होंने 2 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक अंबिकापुर के लखनपुर में मंत्री राजेश अग्रवाल के निवास/क्षेत्र में कथा संपन्न की थी।

कथावाचक ने दावा किया है कि वह वर्तमान में राजधानी रायपुर में विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अपमान से आहत होकर उनके पास अब आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस धमकी के बाद विधानसभा परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।

आरोपों पर प्रतिक्रिया का इंतजार

इस हाई-प्रोफाइल मामले में अभी तक मंत्री राजेश अग्रवाल या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या यह कोई आपसी लेन-देन का विवाद है या इसके पीछे कुछ अन्य कारण हैं। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार की 'सनातन' छवि पर सवाल उठाने की तैयारी में हैं।

'कलेक्टर आए हैं तो कहीं अमर जी की सीट खतरे में न पड़ जाए'

शहर सत्ता/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम अपने बेबाक अंदाज और हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। शनिवार को बिलासपुर में आयोजित गोधन योजना के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहर के कद्दावर विधायक अमर अग्रवाल पर ऐसी चुटकी ली कि पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री ने मंच से मुस्कुराते हुए कहा, "कलेक्टर संजय अग्रवाल यहां आ गए हैं, तो कहीं अमर जी की सीट खतरे में न पड़ जाए।" मंत्री नेताम के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसके कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं।

मंत्री रामविचार नेताम की चुटकी से सियासी हलचल

पुरानी 'नाराजगी' और नया तंज

राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को पिछले साल दिसंबर में हुए एक घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं। राज्य युवा महोत्सव के दौरान विधायक अमर अग्रवाल मंच पर बैठने की व्यवस्था (प्रोफाइलिंग) को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल से नाराज हो गए थे। उस समय पीछे की लाइन में जगह मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें फ्रंट लाइन पर बुलाया था। शनिवार को जब मंच पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संबोधन शुरू हुआ, तो रामविचार नेताम ने कलेक्टर संजय अग्रवाल की कार्यशैली की तारीफ करते हुए उन्हें 'लोकप्रिय' बताया और मजाकिया लहजे में विधायक की सीट को लेकर यह टिप्पणी कर दी।

कलेक्टर की तारीफ भी और इशारा भी

अपने संबोधन में मंत्री नेताम ने न केवल चुटकी ली, बल्कि कलेक्टर संजय अग्रवाल के काम की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि कलेक्टर जिले में बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और जनता के बीच उनकी पहचान बढ़ रही है। हालांकि, 'सीट खतरे में' वाली बात ने अमर अग्रवाल के समर्थकों और विपक्षी खेमे के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। बता दें कि दिसंबर के विवाद के बाद अमर अग्रवाल ने स्पष्ट किया था कि उनकी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है और वे केवल व्यवस्था का पालन चाहते हैं। शनिवार के कार्यक्रम में भी वे मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे, लेकिन मंत्री नेताम के इस तंज ने पुराने घावों पर मरहम लगाया या नमक छिड़का, यह शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

देवी-देवताओं के अपमान पर बजरंग दल ने दर्ज की शिकायत

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर के राजातालाब इलाके में एक युवक ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं और हिंदुत्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद तनाव का माहौल है। यह मामला तब और बढ़ गया जब युवक का स्टेटस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर आक्रोशित बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने रविवार को थाना जाकर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, राजातालाब निवासी युवक ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर रमजान की शुभकामनाओं के साथ भगवान पर टिप्पणी की और हिंदुओं को काफिर बोला। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आरोपी ने जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यह टिप्पणी की है।इस टिप्पणी के वायरल होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। संगठन ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर सभी हिंदू धर्मावलंबियों से रविवार सुबह सिविल लाइन थाना पहुंचने की अपील की।

NSUI का दावा- 'जो रात भर WhatsApp पर तैरा, वही सुबह परीक्षा में आया'

सीजी 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर लीक!

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बीच 'पेपर लीक' के दावों ने प्रदेश के शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया है। छात्र संगठन एनएसयूआई ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि 14 मार्च को हुई हिंदी विषय की परीक्षा का प्रश्नपत्र एग्जाम से ठीक एक रात पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। एनएसयूआई नेता पुनेश्वर लहरे ने इसे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए मंडल की सुरक्षा व्यवस्था और गोपनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

रात को मोबाइल पर, सुबह डेस्क पर

NSUI नेता पुनेश्वर लहरे के मुताबिक, 13 मार्च की रात से ही व्हाट्सएप ग्रुपों में एक प्रश्नपत्र तेजी से वायरल हो रहा था। जब 14 मार्च को छात्र परीक्षा हॉल में पहुंचे, तो उनके सामने वही सेट आया जो रात भर मोबाइल स्क्रीन पर घूम रहा था। एनएसयूआई का दावा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि वायरल पेपर और मुख्य परीक्षा का पेपर हूबहू एक ही थे। इस मामले ने उन लाखों परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है, जो साल भर कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं। एनएसयूआई ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई हो। वायरल पेपर और वास्तविक पेपर का मिलान कर शासन अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

घेराव की तैयारी: थमेगा माशिमं का कामकाज

इस कथित पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो सोमवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) कार्यालय का उग्र घेराव किया जाएगा। एनएसयूआई का कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता और सिस्टम की खामियां उजागर नहीं होतीं, उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस गंभीर आरोप के बाद अब सबकी नजरें माध्यमिक शिक्षा मंडल के बयान पर टिकी हैं। क्या मंडल आंतरिक जांच के आदेश देगा या इन दावों को सिरे से खारिज करेगा? यह आने वाले 24 घंटों में साफ हो जाएगा।

आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत करेगी एमबीबीएस योजना

प्रदेशभर के सभी बिजली वितरण केंद्रों व कार्यालयों में पंजीयन हुआ शुरू

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (एमबीबीएस) आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत और संजीवनी बनकर सामने आई है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी तथा अन्य कारणों से बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को सीधे राहत प्रदान की जाएगी।

यह योजना विशेष रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2023 की स्थिति में बकाया राशि को आधार मानकर उपभोक्ताओं को मूल राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। प्रदेश के 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत लगभग 758 करोड़ रुपए तक की सीधी छूट मिलने का अनुमान है। बिजली क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि की राहत पहली बार दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के दौरान प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों के कारण कई महीनों तक मीटर रीडिंग नहीं हो पाई थी। इसके चलते बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल मिले, जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण वे जमा नहीं कर सके। महामारी के कारण कमजोर हुई आर्थिक स्थिति ने अनेक परिवारों को और अधिक कठिनाई में डाल दिया। ऐसे ही उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।

पुराने बकाये का निराकरण करने का अवसर

इस योजना से उपभोक्ताओं को न केवल बकाया बिजली बिलों के भुगतान में राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें सरल और सुविधाजनक तरीके से अपने पुराने बकाये का निराकरण करने का अवसर भी मिलेगा। योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता मोर बिजली ऐप, सभी बिजली वितरण केंद्रों तथा संबंधित कार्यालयों में पंजीयन करा सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें। भुगतान के बाद पात्र उपभोक्ताओं को एम-ऊर्जा योजना का लाभ भी मिलने लगेगा।

लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना न केवल लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देगी, बल्कि उन्हें नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करेगी।

मुख्यमंत्री साय की इस संवेदनशील पहल से प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय पर पंजीयन कर योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें तथा भुगतान के दौरान किसी प्रकार की आशंका होने पर संबंधित वितरण केंद्र के अधिकारियों से संपर्क किया जाए।

दंतेवाड़ा में मिलेट्स खेती बन रही किसानों की नई पहचान

शहर सत्ता/रायपुर। मिलेट्स (मोटा अनाज) की खेती कम लागत, कम पानी और बिना रसायनों के होने वाली एक अत्यधिक लाभदायक व पौष्टिक खेती है, जो 80-90 दिनों (जून-जुलाई से) में तैयार होती है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी जैसे मिलेट्स बंजर या कम उपजाऊ भूमि के लिए भी उपयुक्त हैं। दंतेवाड़ा जिला अब मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की जा रही है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग के प्रयासों से अब किसान पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद मिल रही है। दंतेवाड़ा जिले के कृषि इतिहास में पहली बार लगभग 300 प्रगतिशील किसान उन्नत 'श्री विधि' से रागी (मडिया) की खेती कर रहे हैं। इस नई पद्धति से रागी उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पोषक अनाजों की खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। रागी को पोषण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस पहल को सफल बनाने के लिए कृषि विभाग और भूमगादी की टीम गांव-गांव जाकर किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दे रही है। किसानों को बुवाई की सही विधि, पौधों के बीच उचित दूरी, जैविक खाद का उपयोग और फसल प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। इससे किसानों में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के प्रति उत्साह बढ़ रहा है।

पर्यटन को नया पंख: धमनी ईको टूरिज्म ग्राम में नौका विहार सुविधा

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों की आजीविका सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वनमण्डल बलौदाबाजार अंतर्गत ईको-पर्यटन ग्राम धमनी में नौकाविहार सुविधा का शुभारंभ किया गया। महानदी के रमणीय तट पर शुरू की गई इस नई सुविधा से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने के साथ-साथ वन प्रबंधन समितियों और स्थानीय ग्रामीणों के लिए आय के नए अवसर भी विकसित होंगे। वनमण्डलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि ईको-पर्यटन गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनसहभागिता के माध्यम से प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए धमनी क्षेत्र को एक आदर्श ईको-पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वन प्रबंधन समितियों की आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ईको-पर्यटन गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। धमनी को एक मॉडल ईको-विलेज के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी है, जहाँ प्रकृति आधारित पर्यटन की विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही पर्यटकों के ठहरने के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएँ विकसित की जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक वातावरण के बीच पर्यटन का अनुभव और अधिक आकर्षक व यादगार बनाया जा सके। महानदी के तट पर स्थित धमनी का प्राकृतिक सौंदर्य लंबे समय से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।

पत्रकारों के लिए विशेष स्क्रीनिंग 21 मार्च को

'बीरनपुर फाइल्स' में दिखेगी बीरनपुर की सच्चाई

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित बीरनपुर कांड पर आधारित फिल्म "बीरनपुर फाइल्स" अब दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। सेंसर बोर्ड की आवश्यक औपचारिकताओं के कारण लंबे समय से अटकी यह फिल्म अब रिलीज के लिए हरी झंडी पा चुकी है। संभावना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में यह फिल्म दर्शकों को देखने को मिलेगी। सत्य घटना पर आधारित यह फिल्म बीरनपुर कांड की पूरी कहानी को पर्दे पर प्रस्तुत करती है। इस घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक परिदृश्य में व्यापक हलचल मचाई थी। फिल्म के माध्यम से न केवल हत्याकांड की घटनाओं को प्रभावी ढंग से दिखाने का प्रयास किया गया है, बल्कि उससे जुड़े कई अनछुए पहलुओं और अपराधियों की भूमिका को भी सामने लाने की कोशिश की गई है। फिल्म का निर्माण व्हाय आर फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। निर्माता-निर्देशक हेमलाल चतुर्वेदी

की यह कृति लगभग दो वर्ष पहले बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन सत्य घटनाओं पर आधारित होने के कारण आवश्यक नियमों और औपचारिकताओं के चलते इसकी रिलीज में विलंब हुआ।

फिल्म के निर्माता-निर्देशक हेमलाल चतुर्वेदी एवं राष्ट्रवादी पत्रकार राष्ट्रबोध के संपादक पवन केसवानी ने आज रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी से भेंट कर फिल्म की विषय-वस्तु और इसकी उपयोगिता के संबंध में चर्चा की। इस मौके पर फिल्म के निर्माता-निर्देशक ने प्रेस क्लब पहुंचकर अध्यक्ष मोहन तिवारी, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव भूपेन जांगड़े तथा वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी में "बीरनपुर फाइल्स" का पोस्टर भी लॉन्च किया। साथ ही पत्रकारों को विशेष स्क्रीनिंग के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया। पत्रकारों के लिए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग 21 मार्च को रायपुर के विमतरा हॉल में आयोजित की जाएगी। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने फिल्म निर्माण के लिए चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने पत्रकार साथियों से अपील की है कि वे 21 मार्च को आयोजित विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होकर फिल्म देखें और अपनी समीक्षा के माध्यम से पाठकों एवं दर्शकों को इस फिल्म के बारे में अवगत कराएं, इस मौके में प्रेस क्लब के पदाधिकारी गणों के साथ वरिष्ठ पत्रकार कमलेश गोगिया, शंकर चंद्राकर , मुकेश वर्मा, जगजीत सिंह, साजिद, संतोष साहू , हेमंत डोंगरे, मौजूद थे

धुरंधर-2 के बाद क्या आएगी'धुरंधर-3'

19 मार्च को रिलीज हो रही है ब्लाकबस्टर फिल्म का सिक्वल

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी वक्त से एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, उससे पहले तरह-तरह के अपडेट्स सामने आ रहे हैं. धुरंधर जब रिलीज हुई थी, तभी हिंट मिल गया था कि मेकर्स धुरंधर 2 भी लेकर आएंगे. वहीं अब 19 मार्च को धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है. ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि धुरंधर 3 बनेगी या नहीं. चलिए जानते हैं आदित्य धर ने पार्ट 3 को लेकर क्या कहा है.

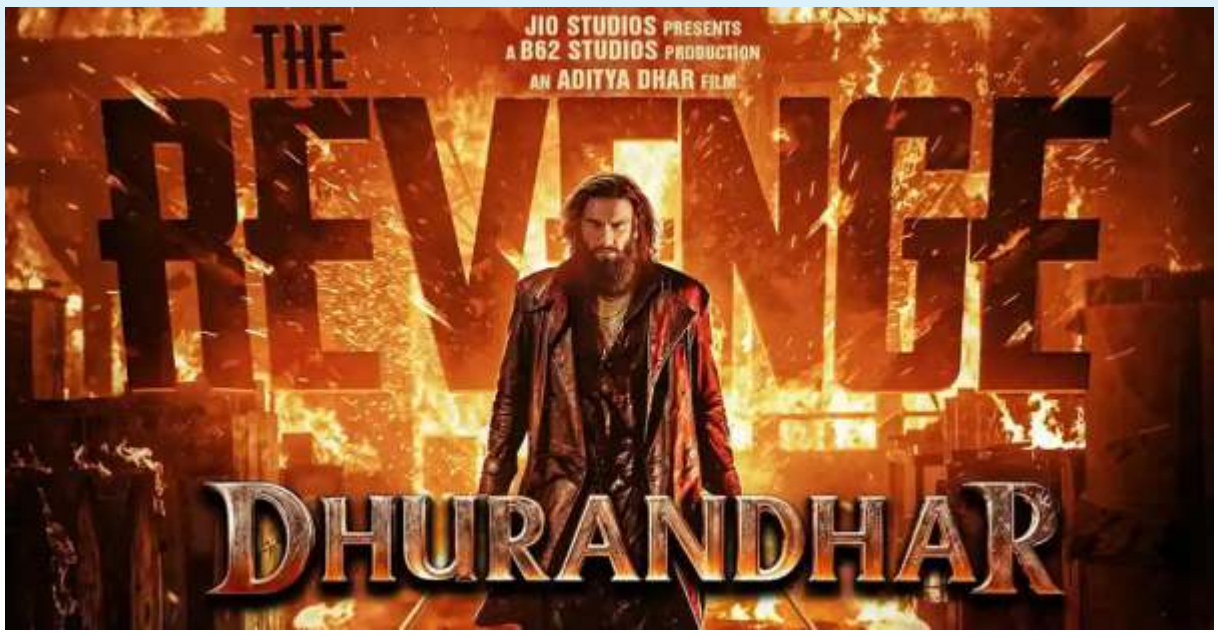

वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर द रिवेंज वो रिलीज से पहले ही काफी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में इस यूनिवर्स को मेकर्स और भी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं. रिपोर्ट पर गौर करें तो आदित्य धर से स्टूडियो चाहता है कि धुरंधर 3 पर भी काम हो. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, जिसपर कई पार्ट्स बनाए जा सकते हैं. यही वजह है कि कहीं ना कहीं तीसरे पार्ट काम करने की संभावना से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता है. रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि आदित्य के पास पहले से ही पार्ट 3 के लिए आइडिया है. हालांकि, इसको लेकर अभी तक उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है. दूसरी तरफ स्टूडियो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है. यही वजह है कि दर्शकों की एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए उसने मेकर्स से कम से कम एक पोस्ट क्रेडिट टीजर में शामिल करने के लिए कहा है, जिससे फैंस को तीसरे पार्ट की संभावना का संकेत मिले. वहीं, आदित्य धर फिल्मों की फ्रेंचाइजी पर काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं. उन्हें फ्रेंचाइजी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इन सबके बावजूद वो नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद करते हैं.

BAFTA अवॉर्ड के बाद 'बूंग' ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड

BAFTA अवॉर्ड अपने नाम करने वाली मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने हाल ही में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 6 मार्च को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने के बाद, इस फिल्म ने 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मणिपुरी फिल्म बन गई है. फिल्म के दोबारा रिलीज होने से न केवल इसकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची, बल्कि भारतीय सिनेमा में इसकी पहचान भी और मजबूत हुई है. 'बूंग' ने बॉक्स ऑफिस पर ये शानदार मुकाम हासिल किया है, जो मणिपुर के क्षेत्रीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी और दुर्लभ उपलब्धि है.

ग्लोबल लेवल पर रच इतिहास

इस शानदार सफर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ते हुए, 'बूंग' ने ग्लोबल लेवल पर भी इतिहास रच दिया है. ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने BAFTA अवॉर्ड जीता है. ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत है जिसने मणिपुरी सिनेमा को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है. ये सम्मान न सिर्फ फिल्म बनाने वालों के लिए, बल्कि पूरे भारतीय फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ा पल है, जो हमारे देश के अलग-अलग कोनों से आने वाली कहानियों की ताकत और विविधता को दिखाता है.

कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई

लक्ष्मीप्रिया देवी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का प्रीमियर सबसे पहले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था. इसके बाद इस फिल्म ने कई बड़े फिल्म फेस्टिवल्स का सफर तय किया, जिनमें वारसॉ, साओ पाउलो, एडिलेड और टालिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल जैसे नाम शामिल हैं. हर जगह इस फिल्म ने अपनी सादगी और दिल छू लेने वाली कहानी की वजह से खूब नाम कमाया.

क्या है फिल्म की कहानी

'बूंग' मणिपुर के एक छोटे से लड़के की कहानी है जिसका किरदार गुगुन किपगेन ने निभाया है. ये लड़का जो अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ना चाहता है. बूंग की परवरिश उसकी सिंगल मदर मंदाकिनी (बाला हिजाम निंगथौजाम) ने की है. वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर अपने लापता पिता को खोजने के एक भावुक सफर पर निकलता है. ये फिल्म उम्मीद, मुश्किलों से लड़ने की ताकत और मां-बेटे के गहरे रिश्ते जैसे बेहद जरूरी मुद्दों को छूती है.

कनाडाई पासपोर्ट लेने के पीछे के राज से अक्षय कुमार ने उठाया पर्दा

अक्षय कुमार के पास 2023 से पहले कनाडा का पासपोर्ट था. ऐसे में उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है. लोग उन्हें तरह-तरह की बातें कहते हैं. अब इस पूरे मामले पर अक्षय कुमार ने अपना रिएक्शन दिया है. साथ ही ये भी बताया कि आखिर उन्होंने कनाडा का पासपोर्ट क्यों लिया था.इतना ही नहीं अक्षय कुमार ने एक और सवाल का जवाब दिया और वो ये था कि क्या वो कैनेडियन कहे जाने की वजह से देशभक्ति फिल्मों में काम कर रहे थे. इंडिया टुडे के एक इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने इस सब मुद्दों पर खुलकर बात की.इस दौरान अक्षय ने कहा,'मैं जो भी काम करता हूं, अपनी छवि बनाने के लिए नहीं करता हूं. मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन देशभक्त की इमेज बनाने के लिए काम नहीं करता हूं. मैं काम करता हूं क्योंकि मुझे जो लगता है कर लेता हूं.'

इसी दौरान अक्षय ने अपने कैनेडियन पासपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा,'वैसे तो मैं ये पहले कई बार कह चुका हूं कि हां कैनेडियन मेरा पासपोर्ट था..क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसा दौर भी आया था, जब लगातार 16-17 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं. काम तो था मेरे पास लेकिन बस 3-4 फिल्में ही बची हुई थीं. ऐसे में मैं सोच रहा था कि क्या करूं. ऐसा नहीं रहै कि हमारे देश से बाहर जाकर लोग काम नहीं करते तो मुझे भी कनाड़ा में काम मिल रहा था, तो मैंने वहां छोटा सा बिजनेस करने का प्लान बनाया था.' अक्षय कुमार ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'उसी दौरान मुझे पासपोर्ट मिल गया. उसके बाद कमाल की बात ये थी कि जो फिल्में मेरी 3 रिलीज होने वाली थी वो तीनों हिट हो गईं. उसके बाद मुझे काम मिलने लग गया.मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि अब नहीं आऊंगा. इंडिया में ही मैं रहूंगा. इस बीच मैं भूल गया और मेरे लिए बस वो एक पासपोर्ट ही था. मैंने इतना नहीं सोचा.'

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए पवन कल्याण

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर एक अलग बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स ने नोटिस किया कि ट्रेलर के एक सीन में पवन कल्याण का लुक उनकी पिछली फिल्म 'दे कॉल हिम OG' से मिलता है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में एक्टर और फिल्म की टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया. ट्रेलर में पवन कल्याण एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में हैं. एक सीन में वह मोनोक्रोम कलर के कपड़े पहनकर हाथ में बंदूक लिए दमदार डायलॉग बोलते दिखाई देते हैं. इस सीन में उनकी बेल्ट का डिजाइन भी अलग है. लेकिन ये लुक देखकर दर्शकों को उनकी 2025 में आई फिल्म 'दे कॉल हिम OG' की याद आ गई, क्योंकि उस फिल्म में भी वह लगभग इसी तरह के कपड़ों में बंदूक चलाते हुए नजर आए थे।

प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व का स्थल मोटियारी घाट

डा पीसी लाल यादव

खैरागढ़ - छुईखदान - गंडई जिला की प्रसिद्धि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के साथ-साथ यहां के पुरातात्विक स्थलों व प्राकृतिक स्थलों के करण भी है। इस जिले में जिन प्राकृतिक स्थलों के सौंदर्य का अवलोकन कर मन प्रसन्न हो जाता है, उनमें मोटियारी घाट-बंजारी माता की प्रमुखता है। मोटियारी घाट गंडई नर्मदा से बालाघाट मध्यप्रदेश राज्य मार्ग पर ग्राम मोहगांव के बाद प्रारंभ होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर बनाई गई सर्पीली सड़क लोगों के मन में कौतूहल और रोमांच पैदा करती है। मोटियारी घाट में अनेक खतरनाक मोड़ हैं। एक ओर ऊंची चट्टानें और दूसरी ओर गहरी खाई तथा दोनों ओर प्रकृति का बिखरा अनुपम सौंदर्य यात्रियों को आनंद से भर देता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चहकती चिड़ियों और वन फूलों की गंध से मनन प्रसन्न हो जाता है।

मोटियारी घाट में राम गोलाई नंगारा डोंगरी के ऊपर बनी वॉच टावर से प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन किया जा सकता है। प्रकृति दर्शन से असीम सुख की प्राप्ति होती है। मोटियारी घाट के नामकरण पर स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि

पहले यह घाट दुर्गम और कठिन था। लोग केवल पैदल यात्रा करते थे, तब घाट चढ़ते समय किसी मोटियारी (युवती) की गिर कर मृत्यु हो गई थी। तब से इसे मोटियारी घाट कहा जाने लगा। घाट के पश्चिम छोर पर बंजारी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इसलिए इसे बंजारी घाट भी कहा जाता है। बंजारी मंदिर में दुर्गा माता की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। यहां पर चैत्र क्वांर माह में दोनों ही नवरात्र के समय ज्योति कलशों की स्थापना होती है। चूंकि यह राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली जाने के मार्ग पर स्थित है। अतः यहां दर्शनार्थियों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। बंजारी मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। बंजारी माता व मोटियारी घाट रमणीय व दर्शनीय स्थल है। यहां काले व लाल मुंह के बंदर पाए जाते हैं, जो सावधान न रहने पर यात्रियों से प्रसाद आदि छीन लेते हैं।

पुराणों में वर्णित है अरपा नदी का महत्व

डॉ. पुष्पा तिवारी

छत्तीसगढ़ में बहने वाली अति प्राचीन कृपा नदी जो वर्तमान में अरपा कहलाती है, बिलासपुर जिले से प्रवाहित होती है, तथा शिवनाथ नदी में समाहित होती है। पुराणों में इसे कृपा नदी कहा गया है जबकि वायु पुराण में कूपा कहा गया है। पुराणों में इस नदी का उदगम शुक्तिमत पर्वत से माना गया है। विद्वानों के अनुसार अरपा ही शिवनाथ की सहायक कृपा नदी है। बिलासपुर इस नदी के तट पर स्थित है एवं यह कर्रा नामक स्थान पर शिवनाथ में विलीन होती है। खारुन नदी दुर्ग के तांदुला नामक स्थान से उद्गमित रायपुर में प्रवाहित होती है तथा शिवनाथ में विलीन होती है। खारुन नदी का उदगम दुर्ग जिले के बालोद तहसील स्थित पटेचुआ नामक स्थान के पास चोरहा नाला के रूप में हुआ है। यह उत्तर में दुर्ग, रायपुर जिलों की सीमा बनाते हुए दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में समाहित हो जाती है। पुराणों में इसे चित्रोत्पला कहा गया है। यह इस क्षेत्र की पावन नदी मानी गई है। वायु पुराण में इसे निलोत्पला कहा गया है। आगे सिहावा पर्वत श्रेणियों से पश्चिम में कांकेर होते हुए चारामा पहुंचती है। यह पूर्वाभिमुख होकर रायपुर बिलासपुर जिलों की सीमा रेखाएं बनाते हुए ओडिशा प्रवेश कर आगे बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। आगे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी होने के कारण महानदी कहलाती है।

आदिवासियों का बिना साज सज्जा दंडार नृत्य

कुसुमलता सिंह

आदिवासी दंडार नृत्य में पहला नमन हनुमान जी को, दूसरा नमन बिरसन देव, तीसरा नमन बड़ादेव और चौथा नमन गणेश जी को करते हैं। बैगा, भील, मुरिया, कोरकू, कोल और माडिया नृत्य के समय कोई साज सज्जा नहीं करते। पर्व तथा अन्य अवसरों पर किए जाने वाले नृत्यों में भी साज सज्जा नहीं करते। इसलिए इन्हें किसी भी समय नृत्य करने में दिक्कत नहीं होती। इस कारण इनके नृत्य अत्यधिक आकर्षक और दर्शनीय होते हैं। जनजातीय नृत्य आद्य कला के प्रमाणित दस्तावेज है। आधुनिक प्रभावों के कारण निरंतर बदलती जीवन शैली के कारण आदिम नृत्यों में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। फिर भी अभी ऐसी कई आदिम जनजातियों में कमार, कोरवा, अबूझमाडिया ने अपनी पारंपरिक शैली में परिवर्तन होने से बचाया है। आदिम नृत्यों में आनंद की अभिव्यक्ति मुद्राओं, प्रतीकों और लय ताल की तन्मयता में अधिक होती है।

रमदहा प्रपात में प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा

कोरिया जिला मुख्यालय से 130 कि मी दूरी पर बैकुंठपुर, कठौतिया, चुटकी और भंवरखोल होते हुए मदहा प्रपात पहुंचा जाता है। बनास नदी पर चारों ओर पहाड़ों तथा जंगल से घिरा सुंदर इस प्राकृतिक स्थान में गर्मियों के दिनों में भी पर्याप्त पानी रहता है।

श्यामवर्णीय चट्टानों से घिरा यह पर्वत जिसमें पानी रिसकर तथा प्रपात के रुप में लगभग 70 फीट ऊंचाई से गिरता है तथा एक बड़े तालाब अथवा झील में एकत्रित होकर पत्थरों से होता आगे बढ़ता है। बरसात के दिनों में यह स्थल और मनोरम हो जाता है। यहां एक शिवजी का प्राचीन मंदिर है जिसकी मान्यता भी अधिक है। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ होने के साथ ही एक छोटी नदी भी रास्ते में होने के कारण पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है फिर भी यहां की खूबसूरती को देखने पहुंचते ही हैं।

न एड्रेस इंडेक्स, न टैक्स
क्या अपराध को मिल रहा है बढ़ावा!

रायपुर समेत राज्य की सड़कों पर 'बाहरी' गाड़ियों का कब्जा

प्रमुख संवाददाता/विकास यादव

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गाड़ियों का काफिला हर दिन लंबा होता जा रहा है। आंकड़ों की मानें तो पिछले साल की तुलना में इस साल गाड़ियों की बिक्री में 10.18 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया है, लेकिन इस चमक-धमक के पीछे एक गहरा काला सच भी छिपा है। शोरूम से निकलने वाली नई गाड़ियों के साथ-साथ शहर की सड़कों पर दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों की बाढ़ आ गई है। हैरानी की बात यह है कि जहां वैध गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं MP, MH, DL, UP और JH जैसे राज्यों से लाई गई हजारों गाड़ियां बिना 'एड्रेस इंडेक्स' और बिना 'स्टेट रजिस्ट्रेशन' के धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। यह न केवल राज्य शासन के खजाने को करोड़ों का चूना लगा रही हैं, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक 'टाइम बम' की तरह हैं। आखिर आरटीओ और पुलिस की नाक के नीचे सेकंड हैंड और मॉडिफाइड गाड़ियों का यह अवैध कारोबार कैसे फल-फूल रहा है! आज की विशेष रिपोर्ट इसी 'अदृश्य' ट्रैफिक और उससे जुड़े बड़े खतरों पर...

रायपुर। रायपुर में वर्तमान में हजारों की संख्या में ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जिनका पंजीकरण दूसरे राज्यों का है। एक अनुमान के मुताबिक, शहर की कुल बाहरी गाड़ियों में से 80% से अधिक ने स्थानीय आरटीओ में अपना विवरण दर्ज नहीं कराया है। ये गाड़ियां सड़कों पर तो दौड़ रही हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इनका स्थानीय पता 'लापता' है।

सबसे ज्यादा इन राज्यों की गाड़ियां

राजधानी समेत प्रदेशभर की सड़कों पर सबसे ज्यादा दबदबा इन राज्यों की गाड़ियों का है: मध्य प्रदेश (MP), महाराष्ट्र (MH), दिल्ली (DL), झारखंड (JH), बिहार (BR) और उत्तर प्रदेश (UP)। इन राज्यों से गाड़ियां कम कीमत पर खरीदकर लाई जाती हैं और यहां बिना कागजी औपचारिकता के चलाई जा रही हैं।

क्या है एड्रेस इंडेक्स और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

नियम के मुताबिक, यदि कोई बाहरी राज्य की गाड़ी छत्तीसगढ़ में 12 महीने से अधिक समय तक रहती है, तो: उसे मूल राज्य से NOC लेकर छत्तीसगढ़ आरटीओ में 'एड्रेस इंडेक्स' कराना अनिवार्य है। गाड़ी का स्थानीय पता दर्ज होने के बाद यहां का रोड टैक्स पटाना होता है, जिसके बाद उसे CG नंबर अलॉट किया जाता है।

जुर्माना और सजा का प्रावधान

नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है:

जुर्माना : बिना वैध पंजीकरण के गाड़ी चलाने पर 2,000 से 5,000 रुपये तक का चालान।

टैक्स चोरी : रोड टैक्स न पटाने पर टैक्स की राशि पर भारी पेनाल्टी।

जब्ती : बार-बार नियम तोड़ने पर परिवहन विभाग गाड़ी को राजसात (Seize) कर सकता है।

सेकंड हैंड और मॉडिफाइड गाड़ियों का 'अवैध' बाजार

शहर के कई इलाकों में बाहरी राज्यों की सेकंड हैंड गाड़ियां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। दिल्ली और हरियाणा से मॉडिफाइड गाड़ियां (जैसे थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर) लाकर यहां ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन बदले ही इनका सौदा हो जाता है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है।

संभावित अपराधों में बाहरी गाड़ियों का इस्तेमाल

पुलिस विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा है। शहर में होने वाली लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग और नशे की तस्करी जैसे अपराधों में अक्सर बाहरी राज्यों की गाड़ियों का उपयोग होता है। चूंकि इनका एड्रेस इंडेक्स नहीं होता, इसलिए वारदात के बाद आरोपी को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है।

अब तक की कार्रवाई और आंकड़े

आंकड़ों की बात करें तो रायपुर में एड्रेस इंडेक्स कराने वालों की संख्या बेहद कम है। हालांकि, परिवहन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड ने हाल के दिनों में जांच तेज की है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी हजारों गाड़ियाँ पकड़ से बाहर हैं।

राजस्व का गणित

रायपुर में गाड़ियों की बिक्री में 10.18% की वृद्धि यह बताती है कि शहर में क्रय शक्ति बढ़ी है। लेकिन जब बाहरी गाड़ी का रोड टैक्स छत्तीसगढ़ में जमा नहीं होता, तो यह सीधा-सीधा राज्य के विकास फंड का नुकसान है।

तुलनात्मक विश्लेषण

एक तरफ स्थानीय निवासी नई गाड़ी पर भारी टैक्स चुका रहा है, वहीं दूसरी ओर बाहरी राज्यों से गाड़ियाँ लाकर चलाने वाले लोग बिना टैक्स चुकाए सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27